मूल्य 1 रु.
वर्षः 9 - अंक : 300, मुंबई, सोमवार, 17 फरवरी, 2020 ■ RNI.NO. MAHHIN/2010/34146 ■ संपादकः दिलशाद एस. खान

दैनिक मुंबई हलचल

भारत सरकार द्वारा विज्ञापन हेतु मान्यता प्राप्त ®

अब हर सच होगा उजागर

आप की सरकार

सिसोदिया समेत 6 मंत्रियों ने शपथ ली, गोपाल राय ने आजादी के शहीदों और राजेंद्र गौतम ने बुद्ध के नाम पर शपथ ली

नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल ने रविवार को तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके बाद मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और राजेंद्र पाल गौतम ने मंत्री पद की शपथ ली। कांग्रेस की शीला दीक्षित के बाद केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले दूसरे नेता हैं। उन्होंने कहा कि मैं सबका मुख्यमंत्री हूं। कोई भी काम हो तो सीधे मेरे पास आएं। (शेष पृष्ठ 5 पर)

खास मेहमानों को न्योता

जिन खास लोगों को न्योता दिया गया है, उनमें टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल, दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ कर आईआईटी परीक्षा पास करने वाले विजय कुमार, मोहल्ला क्लीनिक की डॉक्टर अल्का, बाइक एंबुलेंस सेवा चलाने वाले युद्धिष्ठिर राठी, नाइट शेल्टर में केयरटेकर शबीना नाज, बस मार्शल अरुण कुमार, सिग्नेचर ब्रिज के आर्किटेक्ट रतन जमशेद बाटलीबोइ और मेट्रो पायलट निधि गुप्ता शामिल हैं।

केजरीवाल ने तीसरी बार सीएम पद की शपथ ली

2 बार प्रधानमंत्री का जिक्र किया

कहा– दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए उनका आशीर्वाद चाहता हूं

देवेंद्र फडणवीस की चुनौती

दम है फिर से कराएं चुनाव

शिवसेना-कांग्रेस और एनसीपी को अकेले हराएगी बीजेपी

मुंबई। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में सबकुछ ठीक-ठाक नहीं चलने की चर्चाओं के बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फड़णवीस ने विपक्षी दलों को चुनौती दी है। फडणवीस ने शनिवार को कहा कि राज्य में सत्तारूढ़ वर्तमान गठबंधन में अगर दम है तो फिर से चुनाव करा ले। बीजेपी अकेले ही कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना को हरा देगी। (शेष पृष्ठ 5 पर)

॥शुभ लाभ॥
MIX MITHAI
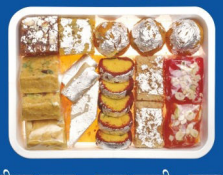
• मोतीचूर लड्डू • काजू कतरी • काजू रोल
• बदाम बर्फी • मलाई पेड़े • रसगुल्ले
MM MITHAIWALA
Malad (W) Tel. : 288 99 501

सीएए पर चर्चा के लिए शाह से मिलने जा रहे शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी लौटाए गए, कहा– अप्वाइंटमेंट दिया जाएगा

प्रदर्शनकारियों ने 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने-बातचीत करने का न्योता दिया था

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर चर्चा के लिए गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने उनके बंगले पर जा रहे शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को वापस लौटा दिया गया है। हालांकि, प्रदर्शनकारियों से कहा गया है कि उन्हें आधिकारिक तौर पर अप्वाइंटमेंट दिया जाएगा। सीएए को लेकर दो दिन पहले एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा था कि इसके खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध करना लोगों का अधिकार है। (शेष पृष्ठ 5 पर)

दैनिक मुंबई हलचल
अब हर सच होगा उजागर

संक्षिप्त खबर

अब ट्रेन चलाने से पहले मेडिटेशन करेंगे मोटरमैन

मुंबई। इस शहर में रोजाना तीन हजार से ज्यादा लोकल ट्रेनें लगभग 24 घंटे चलती हैं। ट्रैक पर रोजाना औसतन दस लोगों की मौत हो जाती है। इनमें से कई लोगों की मौत पटरी पार करने के दौरान कटकर हो जाती है। सुबह और शाम के पीक ऑवर्स के दौरान हजारों लोगों की भीड़ को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाने वाले मोटरमैन दिनभर पूरे तनाव में रहकर लोकल चलाते हैं। पिछले कुछ समय में मोटरमैनों द्वारा स्पैड की घटनाएं भी बढ़ गई थीं। स्पैड का मतलब है प्लैटफॉर्म तक ट्रेन पहुंचने के बाद तय किए गए निशान से आगे यदि लोकल ट्रेन रोकी गई हैं, तो यह खतरनाक हो सकता है। इसमें सिग्नलिंग प्रणाली प्रभावित है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी रविंद्र भाकर के अनुसार, 'चर्चगेट स्थित मेडिटेशन रूम में शांतिदायक प्रकाश व्यवस्था, कैंडिलों, आकर्षक पेंटिंगों और बैठने की बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। इसमें मोटरमैन और गार्ड लोकल ट्रेन चलाने से पूर्व कुछ मिनट प्रेक्षा ध्यान कर सकते हैं।'
पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक आलोक कंसल और डीआरएम जी.वी.एल. सत्य कुमार द्वारा मेडिटेशन रूम के अलावा भी मोटरमैन और गार्ड के लिए सुविधाएं शुरू की गई। चर्चगेट स्टेशन पर बने वर्तमान क्षेत्रफल 858 वर्ग मीटर में 462 वर्ग फीट अतिरिक्त जगह जोड़कर 1320 वर्ग फीट में मोटरमैन/गार्ड लॉबी को रिनोवेट कर विस्तार किया गया है। यहां शतरंज और कैरम जैसे इंडोर गेम उपलब्ध कराए गए हैं।

अस्पतालों में बढ़ेगी मरीजों की मुसीबत

मुंबई। दवा सप्लायरों ने गुरुवार से सरकारी अस्पतालों में सप्लाई रोक दी है। इसके कारण मरीजों को मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन का दावा है कि सप्लायर्स के फैसले से लोकल पर्चेज के जरिए होने वाली केवल 10 प्रतिशत आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। बाकी के 90 प्रतिशत की आपूर्ति टेंडर से होती है, जो इससे नहीं प्रभावित होगी। हालांकि दवा सप्लायर का कहना है कि वे किसी भी तरह की सप्लाई नहीं कर रहे हैं।
ऑल फूड ऐंड ड्रग लाइसेंस होल्डर फाउंडेशन (एएफडीएलएचएफ) के सदस्यों न बताया कि गुरुवार से उन्हें जेजे, कामा, जीटी, सेंट जॉर्ज सहित दूसरे सरकारी अस्पतालों से ऑर्डर मिल रहे हैं। लेकिन बकाया राशि न मिलने के कारण वे ऑर्डर नहीं ले पा रहे हैं। एएफडीएलएचएफ अभय पांडेय ने कहा कि हमारे पास इतने भी पैसे नहीं है कि हम मिलने वाले ऑर्डर को सप्लाई कर सकें।
फाउंडेशन से जुड़े एक सदस्य ने कहा कि शनिवार या रविवार से अस्पतालों में दवाओं सहित दूसरी जरूरी चीजों की भारी किल्लत हो सकती है।
दवाओं की समस्या को लेकर जब एनबीटी ने डायरेक्ट्रेट ऑफ मेडिकल एजूकेशन ऐंड रिसर्च (डीएमईआर) से बात की तो डीएमईआर के डायरेक्टर डॉ. टीपी लहाने ने कहा कि लोकल स्तर पर हम केवल 10 प्रतिशत दवाओं की खरीदारी करते हैं। बाकी की खरीदारी टेंडर के जरिए होती है, जिसका स्टॉक अस्पताल में है। इसलिए दवा को लेकर किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि इस पर एएफडीएलएचएफ के अध्यक्ष अभय पांडेय ने कहा कि राज्य में सरकारी अस्पतालों में दवा सप्लाई करने वाले तकरीबन 150 लोग हैं, जो हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं।
यही वे सप्लायर हैं जो लोकल में भी दवा उपलब्ध कराते हैं और टेंडर के जरिए भी। जब तक बकाया राशि का भुगतान हमें नहीं होता हम किसी भी तरह की सप्लाई नहीं कर पाएंगे। फिर चाहे लोकल पर्चेजिंग के जरिए हो या टेंडर के जरिए।

एल्गार परिषद केस: एनआईए जांच के मुद्दे पर सीएम उद्धव पर बरसे शरद पवार

कोल्हापुर/मुंबई। महाराष्ट्र के एल्गार परिषद केस की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनसीपी) को सौंप दी गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख शरद पवार ने इस फैसले को लेकर उद्धव ठाकरे सरकार की आलोचना की है। कोल्हापुर में पत्रकारों से बातचीत में शरद पवार ने कहा कि केंद्र सरकार ने मामले की जांच पुणे पुलिस से लेकर एनआईए को सौंपकर ठीक नहीं किया क्योंकि कानून-व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है।

एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा, 'मामले की जांच एनआईए को सौंपकर केंद्र सरकार ने ठीक नहीं किया और इससे भी ज्यादा गलत बात यह हुई कि राज्य सरकार ने इसका समर्थन किया।' गौरतलब है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) शिवसेना के नेतृत्व वाले महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार की सहयोगी है और इसके नेता अनिल देशमुख राज्य

के गृहमंत्री हैं।

इससे पहले एल्गार परिषद मामले की सुनवाई कर रही पुणे की एक अदालत ने एक आदेश पारित करते हुए यह मुकदमा मुंबई की विशेष एनआईए अदालत को सौंप दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस आर नवंदर ने यह आदेश पारित किया। अदालत ने आदेश दिया कि मामले से जुड़े रेकॉर्ड और कार्यवाही मुंबई की विशेष एनआईए अदालत को सौंप दी जाए। अदालत द्वारा आदेश पारित किए जाने से पहले अभियोजन पक्ष ने कहा कि उन्हें राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की उस याचिका पर कोई आपत्ति नहीं है, जिसमें मामला ट्रांसफर किए जाने का अनुरोध किया गया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा, 'इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राज्य जांच एजेंसी यह जांच एनआईए को सौंप रही है। दो दिन पहले उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने कहा था कि इस मामले की जांच एनआईए द्वारा अपने हाथों में लिए जाने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। आदेश में राज्य पुलिस को निर्देश दिया गया था कि वह मामले की जांच से जुड़े सभी दस्तावेज एनआईए को सौंप दे। न्यायाधीश ने यह आदेश भी दिया कि सभी आरोपियों को 28 फरवरी को या उससे पहले मुंबई में विशेष एनआईए अदालत के समक्ष पेश किया जाए।

'किले' की लड़ाई में भाजपा पर भारी पड़ी शिवसेना

मुंबई। बांद्रा किले और गार्डन के विकास के लिए बीएमसी प्रशासन द्वारा लाए गए प्रस्ताव को स्थायी समिति की बैठक में नामंजूर कर दिया गया। इस प्रस्ताव को भाजपा ने समर्थन दिया था, जबकि शिवसेना के नेतृत्व में कांग्रेस-राकांपा ने इसका कड़ा विरोध किया, जिसके कारण यह प्रस्ताव अटक गया। इसे बीएमसी में भाजपा के बड़ा झटका माना जा रहा है, जबकि इस प्रस्ताव के खिलाफ शिवसेना के नेतृत्व में महाविकास आघाडी की एकजुटता साबित हुई है। बांद्रा किले के सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव भाजपा विधायक आशीष शेलार का है। इसी कारण इस प्रस्ताव को स्थायी समिति की बैठक में मंजूरी नहीं मिल सकी। स्थायी समिति अध्यक्ष यशवंत जाधव ने प्रस्ताव पर सवाल उठाते हुए कहा कि सिर्फ बांद्रा ही क्यों सायन, माहिम, वर्ली सहित मुंबई के सभी किलों का संवर्धन और संरक्षण करने की जरूरत है।

बता दें की बीएमसी प्रशासन ने शुक्रवार को बांद्रा किले के सौंदर्यीकरण के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पेश किया। इसके लिए बाकायदा वीडियो के जरिए प्रजेंटेशन भी दिया गया। प्रशासन का कहना था कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक आय में इजाफा होगा। इसका समर्थन करते हुए भाजपा के प्रभाकर शिंदे ने कहा कि बांद्रा में ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे का निवास है इसलिए इस किले के सौंदर्यीकरण का महत्व बढ़ जाता है। आदित्य ठाकरे किलों के संवर्धन के पक्ष में रहे हैं।

वहीं कांग्रेस के स्थानीय नगरसेवक आसिफ जकारिया ने सवाल उठाते हुए कहा कि किले के संवर्धन के लिए क्या मैरीटाइम बोर्ड और एएसआई से अनुमति ली गई है। गार्डन के सौंदर्यीकरण के लिए 7 से 8 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं यह सिर्फ लादी हटा कर होगा या वाकई कमा होगा। साढ़े पांच करोड़ रुपये लाइटिंग पर खर्च किए जाने हैं, साथ ही साइकल ट्रैक बनाने की बात कही गई है। इसकी कोई प्लानिंग भी है यह सिर्फ फाइलों में है। उन्होंने कहा कि यहां साढ़े तीन सौ झोपड़े हैं, उनका पुनर्वसन किए बिना कैसे सौंदर्यीकरण होगा।

नेता विपक्ष रवि राजा ने कहा कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सिर्फ बांद्रा किला ही नहीं पूरी मुंबई पर ध्यान देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री का आधिकारिक निवास बांद्रा में नहीं बल्कि बालकेश्वर वर्षा बंगला है। किलों की जमीन का अतिक्रमण कर झोपड़े बने हैं, पहले उनका पुनर्वसन किया जाए फिर मुंबई के सभी किलों के संवर्धन का प्रस्ताव लाया जाए।

दहिसर में नया फायर स्टेशन

मुंबई। राज्य के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने शुक्रवार शाम को दहिसर के कांदरपाडा में नए फायर ब्रिगेड स्टेशन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुंबई का फायर ब्रिगेड के पास दुनिया के आधुनिकतम संसाधन हैं। जिसमें एडवांस फायर फिटिंग सिस्टिम और मानव संसाधन उपलब्ध है। फायर ब्रिगेड के जवानों ने अपनी जान पर खेल कर कई लोगों की जान बचाई है। उन्होंने कहा कि मुंबई फायर ब्रिगेड देश की सबसे बड़ी फायर सिस्टिम है। इसके आधुनिकीकरण में हम हमेशा तत्पर रहे हैं। इस अवसर पर भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी ,स्थानीय भाजपा विधायक मनीषा चौधरी, शिवसेना विधायक विलास पोतनीस व अन्य मौजूद थे।

तत्काल टिकट में गड़बड़ी करनेवालों की खैर नहीं,

300 गिरफ्तार, 21 लाख के टिकट सीज

मुंबई। रेलवे के तत्काल टिकट की बुकिंग में गड़बड़ी करने वाले गिरोह का पदार्फाश दो हफ्ते पहले किया गया था। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने अब देशभर के अलग-अलग हिस्सों में छापेमारी में 300 एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें से 48 सिर्फ मुंबई से हैं। इन लोगों के पास से लगभग 21 लाख रुपये के टिकट भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि ये लोग ऑनलाइन सिस्टम के बावजूद गलत तरीके से टिकट बुक कर लेते थे और उसे महंगे दामों में बेच देते थे।

जानकारी के मुताबिक, यह गिरोह हर दिन बड़े और महत्वपूर्ण रूट्स के हजारों तत्काल टिकट बुक कर रहा था। जिन 300 एजेंट्स को गिरफ्तार किया

गया है, वे सभी आईआरसीटीसी से अप्रूव्ड हैं। गड़बड़ी करने के लिए ये लोग आईआरसीटीसी के यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ-साथ फर्जी आईडी का इस्तेमाल करते थे। अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके ये लोग कुल उपलब्ध टिकटों के आधे से ज्यादा टिकट सिर्फ 50 सेकंड में ही बुक कर लेते थे।

आरपीएफ के महानिदेशक अरुण कुमार ने बताया, 'सिस्टम में गड़बड़ी करके टिकट बुक करने वाले लोगों के खिलाफ ऐक्शन जारी कर रहेगा। सिर्फ दो दिनों में ही 300 एजेंट्स गिरफ्तार किए गए हैं।' उन्होंने यह भी बताया कि सेंट्रल रेलवे ने अभी तक लगभग 11 लाख रुपये के टिकट भी बरामद कर लिए हैं। वहीं, वेस्टर्न रेलवे ने लगभग 10 लाख रुपये कीमत के टिकट बरामद किए हैं। जनवरी के आखिरी हफ्ते में आरपीएफ ने 26 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस गिरोह के मुखिया की पहचान गुलाम मुस्तफा के रूप में हुई है।

मालिक,मुद्रक,प्रकाशक-**दिलशाद एस खान** द्वारा एस आर प्रिंटिंग प्रेस,मोहन अर्जुन कंपाउंड, वैशाली नगर दहिसर (पूर्व),मुंबई-68 से मुद्रित व मुंबई हलचल,साईं मंगल को ऑ हॉ सो बी-2-301,इस्माइल बाग नियर मालाड शॉपिंग सेंटर, एस वी रोड,मालाड (प) मुंबई से प्रकाशित RNI NO MAHHIN/2010/34146, फोन:**9619102478 /9769659975**
email: mumbaihalchal@gmail com संपादक: **दिलशाद एस खान,** समाचार पत्र में छपे किसी भी समाचार से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। किसी भी विवाद का निपटारा न्याय क्षेत्र मुंबई होगा।

दैनिक
मुंबई हलचल
अब हर सच होगा उजागर

महाराष्ट्र में 1 मई से लागू होगा एनपीआर, उद्धव सरकार में उठे विरोध के सुर, कांग्रेस ने दिखाई आंख

मुंबई। नागरिक संशोधन अधिनियम (सीएए), राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण (एनआरसी) और राष्ट्रीय जनसंख्या सूची (एनपीआर) के देशव्यापी विरोध के बाद भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1 मई से 15 जून तक एनपीआर के तहत सूचनाएं कलेक्ट करने की अधिसूचना जारी की है। हालांकि, इसको लेकर उद्धव सरकार में सहयोगी दलों के बीच तनातनी भी देखने को मिल रही है।

राज्य कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा कि एनपीआर के प्रावधानों पर कांग्रेस का विरोध है। इस संबंध में कांग्रेस के मंत्री सरकार से बात करेंगे। वहीं, शिवसेना सांसद अनिल देसाई ने कहा कि उद्धव साहब ने साफ-साफ कहा है कि एनपीआर अगर जनगणना जैसा ही है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि जनगणना तो हर 10 साल में होती ही है। ऐसे में सहयोगी दलों के बीच खींचतान साफ दिख रही है। एनसीपी ने इस बारे में अभी पत्ते नहीं खोले हैं। बता दें कि एनपीआर के संबंध में महाराष्ट्र सरकार भी जल्द ही

अधिसूचना जारी करेगी। इसकी पुष्टि मुंबई स्थित केंद्रीय जनगणना कार्यालय ने की है।

महाराष्ट्र में एनपीआर लागू करने को लेकर महाविकास आघाडी में तनातनी देखने को मिल रही है। कांग्रेस सीएए, एनआरसी और एनपीआर का खुलकर विरोध कर रही है। वह महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के साथ सरकार में है, लेकिन राज्य में एनपीआर लागू करने का विरोध करेगी। एनसीपी ने इस बारे में पत्ते नहीं खोले हैं। हाल में एनसीपी नेता और राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एनपीआर के विरोधियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान कहा था कि सरकार कानून विशेषज्ञों से विचार-विमर्श कर रही है। शिवसेना इस बारे में मौन है, जिसे एनपीआर को उसका समर्थन माना जा रहा है।

उद्धव साहब ने साफ-साफ कहा है कि एनपीआर अगर जनगणना जैसा ही है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि जनगणना तो हर 10 साल में होती ही है।

-अनिल देसाई (शिवसेना सांसद)

मुंबई में प्रधान जनगणना अधिकारी के कार्यालय में 6 फरवरी को हुई एक बैठक में मनपा आयुक्तों के अलावा राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारी शामिल हुए थे। महाराष्ट्र शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की प्रधान सचिव और केंद्र व राज्य कार्यालय की समन्वयक वल्सा नायर और जनगणना कार्यवाही संचालनालय की संचालक रश्मि झगडे इस बैठक में मौजूद थीं।

विभाग के निदेशक वाई.एस. पाटील के अनुसार, कर्मचारी और अधिकारी घर-घर जाकर 1 मई से 15 जून के बीच एनपीआर के लिए जानकारी एकत्र करेंगे, जबकि अगले साल 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच जनगणना की जाएगी। इसके लिए 3.34 लाख कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत रजिस्ट्रार जनरल ऐंड सेंसस कमिश्नर ने देशभर में अप्रैल से सितंबर तक जनसंख्या सूची को अपडेट करने के लिए एनपीआर लागू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 7 जनवरी को अधिसूचना जारी की गई थी। जनगणना अधिकारियों, कर्मचारियों और पर्यवेक्षकों के लिए एक पुस्तिका में बताया गया है कि एनपीआर कैसे लागू करना है।

विभाजन के बाद से रिफ्यूजी कॉलोनियों में रह रहे शरणार्थियों को मिलेगा जमीन का अधिकार

मुंबई। देश के विभाजन के समय पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए मुंबई में पांच रिफ्यूजी कॉलोनियां बसाई गई थी। अब लगभग 70 सालों के बाद इन सभी शरणार्थियों को जमीन के अधिकार मिलने जा रहे हैं। भूमि स्वामित्व ट्रांसफर की प्रक्रिया को राज्य सरकार ने प्रस्तावित कर दिया है।

सिंधी और पंजाबी शरणार्थियों को विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्निवास) ऐक्ट 1954 के तहत जमीन अलॉट कर दी गई थी। लेकिन सभी प्लॉट अभी भी सरकार के मालिकाना हक में हैं। 2018 में सरकार ने जमीन को मुक्त कराने का फैसला किया, जिससे सभी शरणार्थियों के लिए घर को बेचने तथा बिना किसी बाधा के फिर से डिवेलप

करने का रास्त खुल गया।

महाराष्ट्र में ऐसी 30 रिफ्यूजी कॉलोनी हैं। मुंबई में कुर्ला, मुलुंड, सायन कोलीवाड़ा में एक-एक तथा चेम्बूर में दो कॉलोनी हैं। ऐसे ही कैंप में जन्मे और होटल का काम करने वाले चरणजीत सिंह अबरोल के मुताबिक यह फैसला काफी सहायता करने वाला होगा। उन्होंने कहा, 'आज तक इन कॉलोनियों में रहने वाले लोग खुद को शरणार्थी ही समझते हैं। हमेशा ही घर को खाली कराने या गिराए जाने का खतरा बना रहता है। घरों की हालत भी काफी जर्जर हो चुकी है।'

वहीं माहिम के रहने वाले घनश्याम मुलानी ने कहा कि शहर के शरणार्थी समुदाय के निवासी लगातार नागरिकता कानून पर सरकार के फैसले पर नजर रखे हुए थे। हमारा समुदाय अभी बिखरा हुआ है। हमारा खुद का कोई भी स्टेट नहीं है। जमीन मिलने के बाद हमारी अगली मांग संस्कृति और भाषा को लोकप्रिय बनाने की होगी। मुलुंड कॉलोनी में रहने वाले 56 वर्षीय कमल कोटई ने कहा, 'मैं अपने 89 साल के पिता घनश्यामदास कोटई के लिए बहुत खुश हूं। विभाजन के बाद भारत आने से पहले समुदाय को कितना कुछ छोड़कर आना पड़ा था, यह सब किस्से बचपन से ही सुनते आ रहे हैं।

'मुंबई नहीं छोड़ना' कहकर बॉम्बे हाई कोर्ट के सीनियर जज सत्यरंजन धर्माधिकारी ने दिया इस्तीफा

मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस सत्यरंजन धर्माधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है। जस्टिस धर्माधिकारी ने यह कहते हुए इस्तीफा दिया है कि वह अपने निजी और पारिवारिक कारणों से नहीं चाहते कि उनका महाराष्ट्र से बाहर ट्रांसफर हो। जस्टिस धर्माधिकारी ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है क्योंकि उन्हें किसी दूसरे राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में प्रमोट किया गया था, हालांकि वह मुंबई नहीं छोड़ना चाहते थे।

जस्टिस धर्माधिकारी ने कहा, 'मैंने पूरी तरह से व्यक्तिगत और पारिवारिक मुद्दों के कारण इस्तीफा दिया। मैं मुंबई नहीं छोड़ना चाहता था और वे मुझे मुंबई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में प्रमोट करने को तैयार नहीं थे।' जस्टिस धर्माधिकारी ने कहा कि उन्होंने गुरुवार शाम अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज दिया। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि उनका इस्तीफा स्वीकार हुआ है या नहीं लेकिन जस्टिस धर्माधिकारी ने शुक्रवार को अदालत में वकीलों से कहा कि यह कार्यालय में उनका आखिरी दिन है और वह 17 फरवरी (सोमवार) से उपलब्ध नहीं रहेंगे।

आपको बता दें कि जस्टिस धर्माधिकारी दो साल बाद रिटायर होने वाले थे। जस्टिस धर्माधिकारी ने कहा, 'मुंबई में मेरी कुछ व्यक्तिगत जिम्मेदारियां हैं, यही वजह है कि मैं महाराष्ट्र से बाहर ट्रांसफर नहीं चाहता था।' इससे पहले सुबह जब अधिवक्ता मैथ्यु नेदमपारा ने एक याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए अदालत से अगले हफ्ते की तारीख मांगी, तब जस्टिस धर्माधिकारी ने इस्तीफा देने संबंधी घोषणा की। जस्टिस धर्माधिकारी ने अदालत में कहा, 'मैंने इस्तीफा दे दिया है, आज यहां मेरा अंतिम दिन है।' ऐडवोकेट नेदमपारा ने बाद में कहा, 'जब न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो शुरूआत में मुझे लगा कि ऐसा उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा है।

बीएमसी में भर्ती का दरवाजा खुला

मुंबई। वित्तीय संकट के कारण बीएमसी में कर्मचारियों की रुकी भर्ती को स्थायी समिति ने बदल दिया है। स्थायी समिति ने एक प्रस्ताव पास कर बीएमसी में नई भर्ती का रास्ता कर दिया है। यह भर्ती प्रक्रिया कब शुरू करनी है, इसका अधिकार प्रशासन के पास है, इसलिए तत्काल भर्ती होने की संभावना नहीं है। दो महीने पहले बीएमसी ने 810 लिपिक पद पर भर्ती को मंजूरी दी थी। लेकिन, बजट में आर्थिक स्थिति खराब होने का हवाला देते हुए किसी भी प्रकार की भर्ती पर रोक लगा दी गई थी।

कोरोना वायरसः चीन, जापान...ऑस्ट्रेलिया में फंसे कई भारतीय, वतन वापसी की राह हुई मुश्किल

मुंबई। कोरोना वायरसः चीन, जापान...ऑस्ट्रेलिया में फंसे कई भारतीय, वतन वापसी की राह हुई मुश्किलकोरोना वायरस (कोविड-19) चीन में कहर मचाते हुए धीरे-धीरे दूसरे मुल्कों में भी पैर पसार रहा है। चीन में अब तक कोरोना की वजह से 1500 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना वायरस के खौफ के कारण विदेश में फंसे कई लोगों को भारत लौटने में दिक्कत हो रही है। विदेशों में फंसे लोगों ने भारत सरकार से गुहार लगाई है कि वे कूटनीतिक संबंधों का इस्तेमाल कर उनकी स्वदेश वापसी की राह आसान करे। हालांकि, वतन वापसी की राह उनकी आसान नहीं दिख रही है।

मुंबई के मीरा-रोड के आकाश पाठक पिछले 10 साल से चीन की एक यूनिवर्सिटी में बतौर प्रॉजेक्ट मैनेजर कार्यरत है। एनबीटी से बातचीत में आकाश ने बताया कि वह कोरोना से प्रभावित वुहान शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित 'हेनान प्रोविंस' में रहते हैं। वह बताते हैं चीन की सरकार का प्रयास सराहनीय

है, लेकिन उसके बावजूद भारतीयों सहित नागरिकों को बहुत परेशानी हो रही है। उन्होंने भारत सरकार से भारतीयों को सुरक्षित देश लाने की अपील की है।

मीरा-रोड की सोनाली ठक्कर (24) ह्यडायमंड प्रिंसेस क्रूजह्न में कार्यरत हैं। बीते 3 फरवरी को उनका क्रूज जापान के योकोहामा तट पर पहुंचा। जहाज में 2 भारतीयों सहित लगभग 200 से अधिक लोग 'कोरोना' की चपेट में आ चुके हैं, जिसके कारण जापान सरकार ने एक भी यात्री को जापान की धरती पर उतरने नही दिया। एनबीटी से बातचीत में सोनाली के पिता दिनेश ठक्कर बताते है कि वह लगातार भारत सरकार से सोनाली सहित जहाज पर सवार 138 भारतीय नागरिकों को जल्द वीजा दिलाने में मदद करने की अपील कर रहे हैं। मीरा-रोड के कैप्टन विश्वास (बदला हुआ नाम- नाम न छापने की शर्त पर बताया) विगत डेढ़ दशक से मर्चेंट नेवी में कार्यरत हैं। वह बताते हैं कि कुछ दिन पहले उनका जहाज ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था, जहां उन्होंने वीजा के लिए आवेदन किया था। चूंकि उनका जहाज कोरिया और चीन के होते हुए आया था, इसलिए उन्हें वीजा देने से इनकार कर दिया गया। कैप्टन विश्वास ऑस्ट्रेलिया से भारत आना चाहते हैं।

दैनिक मुंबई हलचल
अब हर सच होगा उजागर

हमारी बात

दूरसंचार क्षेत्र का संकट

एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी समायोजित सकल राजस्व की देनदारी के मामले में दो प्रमुख दूरसंचार कंपनियां जिस संकट से दो-चार हैं, उसके लिए वे खुद भी जिम्मेदार हैं। दूरसंचार कंपनियां सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कोई खामी इसलिए नहीं निकाल सकतीं, क्योंकि उसने तो वही फैसला दिया जो विधिसम्मत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिस संकट से निजी दूरसंचार कंपनियां ग्रस्त हैं, उससे ही सरकारी क्षेत्र की भी कंपनियां ग्रस्त हैं। इनमें से कुछ गैर-दूरसंचार क्षेत्र की भी कंपनियां हैं। दूरसंचार कंपनियों के संकट के लिए एक हद तक नियामक संस्था और सरकारी नौकरशाही भी जिम्मेदार है। क्या यह बेहतर नहीं होता कि दूरसंचार विभाग और दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई समय रहते हस्तक्षेप करते और इस विवाद को सुलझाते कि राजस्व आकलन का उचित तरीका क्या होना चाहिए? यह आश्चर्यजनक है कि एक दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी दोनों में से किसी ने भी यह नहीं समझा कि कंपनियों के राजस्व आकलन के तौर-तरीकों को तर्कसंगत बनाने की जरूरत है। यह मामला कहीं न कहीं यही बताता है कि यदि समय पर चेतने और उपयुक्त कदम उठाने से इनकार किया जाता है तो गंभीर संकट से ही दो-चार होना पड़ता है। यह कम अजीब नहीं कि राजस्व आकलन का सवाल अनसुलझा होने के बाद भी दूरसंचार कंपनियां आपसी प्रतिस्पर्द्धा में बुरी तरह उलझीं। ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता बनाने की उनकी होड़ में ऐसी स्थिति तो बनी कि भारत में मोबाइल सेवाएं दुनिया भर से सस्ती हो गईं, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि उनकी गुणवत्ता का स्तर संतोषजनक नहीं हो सका। ऐसी होड़ का कोई मतलब नहीं कि कंपनियां सेवाओं की गुणवत्ता के साथ ही अपने आर्थिक भविष्य की भी अनदेखी कर दें। फिलहाल यह कहना कठिन है कि सुप्रीम कोर्ट के बकाया राजस्व चुकाने के फैसले के बाद भारती एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया अपनी देनदारी किस तरह चुकाती हैं। चूंकि वोडाफोन-आइडिया पहले से ही गहरे संकट में है, इसलिए उसके बंद होने की भी नौबत आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो उसे कर्ज देने वाले बैंक भी संकट में आ सकते हैं। इतना ही नहीं, ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि देश के दूरसंचार क्षेत्र में दो ही कंपनियां रह जाएं। इस स्थिति में प्रतिस्पर्द्धा का अभाव देखने को मिल सकता है। जो भी हो, एक ऐसे समय जब दुनिया 5-जी सेवाओं की ओर तेजी से कदम बढ़ा रही है, तब अपने देश में दूरसंचार क्षेत्र का संकट से घिरना कोई शुभ संकेत नहीं। बेहतर हो कि सरकार और नियामक संस्था के साथ ही दूरसंचार कंपनियां जरूरी सबक सीखने में और देरी न करें।

कर सरलीकरण की राह पर बढ़े कदम

हाल ही में एक समाचार चैनल के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश प्रत्यक्ष कर सुधार (डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म) की डगर पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में कर प्रणाली को पिछले 4-5 सालों से लगातार सरल बनाया जा रहा है। करदाताओं के अधिकारों को स्पष्टता से परिभाषित करने वाला करदाता चार्टर भी शीघ्र ही लागू करने की योजना है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि देश के 130 करोड़ लोगों में से सिर्फ 1.5 करोड़ लोग ही आयकर देते हैं। स्थिति यह है कि देश के केवल 3 लाख लोगों ने ही अपनी आय 50 लाख रुपए से अधिक घोषित की है। केवल 2200 प्रोफेशनल लोग ही अपनी आय एक करोड़ से अधिक घोषित करते हैं, जबकि पिछले 5 साल में 3 करोड़ लोग व्यापार के सिलसिले में या घूमने के लिए विदेश गए हैं तथा पिछले पांच वर्षों में 1.5 करोड़ से ज्यादा महंगी कारें खरीदी गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बहुत सारे लोगों द्वारा आयकर का भुगतान नहीं किया जाता। ऐसे में उनके कर नहीं देने का भार ईमानदार करदाताओं पर पड़ता है। ऐसे में जरूरी है कि लोग ईमानदारी से कर देने का संकल्प लें। इस परिप्रेक्ष्य में हम यह देखें कि हालिया दौर में प्रत्यक्ष कर सुधार का सिलसिला तेज हुआ है। विगत 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश आम बजट में प्रत्यक्ष कर सुधार की दिशा में तीन अहम बातें उल्लेखनीय रहीं। एक, प्रत्यक्ष कर विवादों के समाधान के लिए 'विवाद से विश्वास योजना। दो, अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए उपभोग खर्च बढ़ाने वाली आयकर की नई व्यवस्था। तीन, करदाताओं के अधिकारों के लिए करदाता चार्टर को लागू करना।

गौरतलब है कि देश में कर सुधार के एक महत्वपूर्ण कदम के तहत वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने हालिया आम बजट में विभिन्न न्यायाधिकरणों में अटके 4,83,000 प्रत्यक्ष कर विवादों के समाधान के लिए योजना की घोषणा की। इसी तारतम्य में उन्होंने प्रत्यक्ष कर विवादों के समाधान की 'विवाद से विश्वास योजना को लागू करने हेतु 5 फरवरी को लोकसभा में एक विधेयक भी पेश किया। फिर अब उसे आकर्षक और व्यापक दायरे वाली योजना बनाने के लिए 12 फरवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। उल्लेखनीय है कि प्रत्यक्ष कर विवादों के मामलों में 30 नवंबर, 2019 तक 9.32 लाख करोड़ रुपए का कर फंसा हुआ है। ऐसे में प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना से आर्थिक सुस्ती से निपटने की डगर पर आगे बढ़ रही देश की अर्थव्यवस्था

को जहां एक बड़ी धनराशि उपलब्ध होगी और मुकदमों पर सरकार का खर्च घटेगा, वहीं चूककर्ता करदाताओं को भी बिना किसी भेदभाव के फॉर्मूला आधारित समाधान मिलेगा और उनके कर भुगतान संबंधी तनाव में कमी आएगी।

इस कर समाधान योजना के तहत करदाता अपनी पिछली अतिरिक्त आय का खुलासा कर सकेंगे। नई प्रत्यक्ष कर समाधान योजना के तहत कमिश्नर अपील, आयकर अपील न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय में लंबित प्रत्यक्ष कर विवादों के साथ-साथ मध्यस्थता व ऋण वसूली पंचाटों में लंबित मुकदमों तथा कर संशोधन और जब्ती के छोटे मामले भी शामिल किए गए हैं। इनके निपटान में ब्याज, जुर्माने और अभियोजन की छूट की पेशकश की गई है। यह योजना 30 जून, 2020 तक जारी रहेगी। यदि कर बकाया केवल विवादित ब्याज और जुर्माने से जुड़ा है तो 31 मार्च तक विवाद का निपटारा करने पर विवादित जुर्माने/ब्याज की 25 फीसदी राशि का भुगतान करना होगा। उसके बाद यह राशि 30 फीसदी हो जाएगी। इसी तरह आयकर भुगतान को सरल बनाने के लिए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020-21 के बजट में आयकरदाताओं को पहली बार दो विकल्प देने की घोषणा की। या तो आयकरदाता पिछले वर्ष के बजट में दी गई निवेश पर आयकर छूटों का लाभ ले सकता है या फिर नए बजट की आयकर छूटों का लाभ ले सकता है। अब 5 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बजट में इस आशय की घोषणा करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण देश के छोटे आयकरदाताओं, नौकरीपेशा (सैलरीड) और निम्न मध्यम वर्ग के अधिकांश लोगों को राहत पहुंचाती नजर आईं। आगामी 01 अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरूआत के साथ देश के इतिहास में पहली बार करदाता चार्टर भी लागू हो जाएगा। ज्ञात हो कि वर्ष 2020-21 के बजट में आयकर अधिनियम में एक नई धारा 119ए जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है। यह धारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को एक करदाता चार्टर अपनाने एवं घोषित करने के लिए अधिकृत करती है। आयकर अधिनियम में नई धारा जोड़े जाने के बाद सीबीडीटी के पास आयकर अधिकारियों को दिशा-निर्देश और आदेश जारी करने की शक्ति मिल जाएगी।

उल्लेखनीय है कि दुनिया भर में 40 से अधिक देशों में ऐसे करदाता चार्टर बने हुए हैं। भारत को अमूमन घरेलू एवं विदेशी करदाता एक आक्रामक कर नियमन वाले देश के रूप में देखते रहे हैं। ऐसे में इस करदाता चार्टर से कर प्रशासन के प्रति करदाताओं का भरोसा बहाल करने में मदद मिलेगी। यहां पर यह बात भी महत्वपूर्ण है कि नए करदाता चार्टर को तैयार करते समय कानून-निर्माताओं को करदाताओं के प्रति एक तरह की जवाबदेही दिखानी होगी। करदाता चार्टर में कर विवरण सूचना की निजता, कारोबार संबंधी आंकड़ों की गोपनीयता और औपचारिक समाधान प्रक्रिया से इतर एक शिकायत निपटान प्रणाली को भी शामिल किया जाना उचित होगा। एक करदाता चार्टर भले ही करदाता को अधिकार दे देगा, लेकिन उसके प्रभावी अमल के लिए लोगों की मानसिकता में बदलाव तथा कर अधिकारियों के भीतर जवाबदेही की भावना लाने की भी जरूरत है। निःसंदेह वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल अपने पहले बजट में अप्रत्यक्ष कर विवादों के समाधान हेतु जिस 'सबका विश्वास योजना को लागू किया था, उसकी बदौलत अप्रत्यक्ष करों से संबंधित करीब 1,89,000 विवादित मामलों का निपटान किया गया है और इससे करीब 35 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिला है। अब यह नई 'विवाद से विश्वास योजना भी 'सबका विश्वास योजना की तरह सफलता की पूरी संभावनाएं रखती है। अभी समय है कि चूककर्ता आयकरदाता इसका लाभ उठा सकते हैं। इस क्रम में इस योजना से जो बड़ी धनराशि जमा होगी, उससे अर्थव्यवस्था को सुस्ती से उबारने में मदद मिल सकती है। हम आशा करें कि कर सरलीकरण की डगर पर आगे बढ़ रहे हमारे देश में तमाम करदाता भी ईमानदारी से कर चुकाने की ओर प्रोत्साहित होंगे। इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार देने में मदद मिलेगी। प्रत्यक्ष कर सरलीकरण की डगर पर कदम आगे बढ़ाते हुए सरकार का जोर विवाद संबंधी मुकदमों में उलझने के बजाय ज्यादा से ज्यादा कर संग्रह पर होना चाहिए। इससे ईमानदार करदाताओं को भी कर के अधिक बोझ से बचाया जा सकेगा।

राष्ट्रीयता की अनदेखी के दुष्परिणाम

भारतीय समाज की कुछ विशेषताएं हजारों वर्षों की सामाजिक यात्रा के कारण उसकी पहचान बन गई है। इस विशिष्ट पहचान को बनाए रखने का अर्थ है राष्ट्रीय होना। अपनी स्थापना के करीब 20 वर्ष बाद कांग्रेस ने ब्रिटिश विरोधी स्वतंत्रता आंदोलन का रूप लिया था। तब कांग्रेस के सभी नेता भारत के परंपरागत समाज की उस विशिष्ट पहचान की साथ खड़े थे, जो वास्तव में सदियों की सामूहिक यात्रा के कारण निर्मित हुई थी और जो अनेक आक्रमणों और संघर्षों-टकरावों के बाद भी टिकी हुई थी। भारत के समाज का एक वैचारिक अधिष्ठान है, जिसका आधार आध्यात्मिक है। इसके कारण भारत का एक व्यक्तित्व और स्वभाव बना। भारत की विशाल भौगोलिक इकाई में रहने वाला विविध जाति-पंथ-

भाषा के नाम से जाना जाने वाला संपूर्ण समाज भारत की इन विशेषताओं को साझा करता है।

भारत के व्यक्तित्व के चार पहलू है। पहला है, एकम सत विप्राः बहुधा वर्दति। भारत ने अपने आचरण से इस बात को सिद्ध किया है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने वर्ष 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजिद धर्म संसद में अपने व्याख्यान में कहा था कि हम सभी मार्गों को सत्य मानकर उनका सम्मान करते हैं। दूसरा है, विविधता के मूल में रही एकता की अनुभूति करना। गुरुदेव रबीद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, अनेकता में एकता देखना और विविधता में ऐक्य प्रस्थापित करना ही भारत का अंतर्निहित धर्म है। भारत विविधता को भेद नहीं मानता और पराए को दुश्मन नहीं समझता। इसीलिए नए मानव समूह के संघात से हम भयभीत नहीं होंगे। उनकी विशेषता को पहचान कर उसे सुरक्षित रखते हुए उन्हें अपने साथ लेने की विलक्षण क्षमता भारत रखता है। तीसरी विशेषता भारत की यह मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। चौथा लक्षण, यहां प्रत्येक व्यक्ति को अपना-अपना 'मुक्ति का मार्ग चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता होना है। भारत का स्वभाव धर्म है। यह धर्म 'रिलीजन अथवा उपासना नहीं है।

दैनिक
मुंबई हलचल
अब हर सच होगा उजागर

समाचार

मुंबई, सोमवार
17 फरवरी, 2020

राज्य में एक मई से लागू हो सकता है एनपीआर

जनगणना अधिकारी ने 20 डीएम के साथ क्रियान्वन को लेकर की बैठक

मुंबई। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) लागू करने को मंजूरी देने की चर्चा है। इसके तहत एक मई से राज्य में रह रहे लोगों की गणना की जाएगी। केंन्द्रीय गृह मंत्रालय ने 1 मई से लेकर 15 जून तक एनपीआर लागू करने की अधिसूचना जारी की हुई है। हालांकि, राज्य सरकार की तरफ से एनपीआर लागू करने संबंधी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस डायरेक्टर रश्मि जगड़े ने महाराष्ट्र सरकार के 20 जिलाधिकारियों और 15 नगर निगम प्रमुख से एनपीआर और जनगणना को लेकर चर्चा की है। इससे माना जा रहा है कि सरकार की तरफ से

इसे लागू करने पर सहमति बन गई है। इसमें एनपीआर के क्रियान्वयन को लेकर रणनीति बनाई गई है। माना जा रहा है कि यह चर्चा सीएम उद्धव ठाकरे से मिली मंजूरी के बाद ही हुई है। सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार जल्द ही इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। महाराष्ट्र में एनपीआर प्रक्रिया के करीब 6 हफ्ते में पूरा होने की उम्मीद की जा रही है।

सूत्रों ने बताया कि सरकारी कर्मचारी 1 मई से लेकर 15 जून के बीच एनपीआर की जानकारी एकत्र करेंगे। जबकि अगले साल 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच जनगणना की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस काम के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 3.34 लाख कर्मचारी नियुक्त किए हैं। इसके लिए सभी जिले के जिलाधिकारियों को अध्यापकों और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को जनगणना संबंधी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। नागरिकता कानून और एनआरपी को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी शुरू से विरोध कर रही है। ऐसे में सीएम उद्धव ठाकरे द्वारा इसे लागू करने को लेकर हरी झंडी दिए जाने के बाद माना जा रहा है कि शिवसेना और कांग्रेस-राकांपा में फिर एक बार मनमुटाव हो सकता है। इससे पहले भीमा कोरेगांव की जांच एनआईए को सौंपे जाने पर राकांपा प्रमुख शरद पवार उद्धव ठाकरे पर नाराजगी जता चुके हैं।

हाईकोर्ट के दूसरे सबसे सीनियर जज जस्टिस धर्माधिकारी ने दिया इस्तीफा

जस्टिस धर्माधिकारी ने कहा- चीफ जस्टिस बनाकर दूसरे राज्य में भेजा जा रहा था मगर मैं मुंबई से बाहर जाना नहीं चाहता, इसलिए फैसला किया

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट के दूसरे सबसे सीनियर जज जस्टिस एससी धर्माधिकारी ने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफे की वजह निजी और पारिवारिक बताई है। जस्टिस धर्माधिकारी ने शुक्रवार को पत्रकारों से कहा कि उन्हें चीफ जस्टिस बनाकर दूसरे राज्य में भेजा जा रहा था, जबकि वह मुंबई नहीं छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा, ' मैंने बिल्कुल निजी और पारिवारिक कारणों से इस्तीफा दिया है। मैं मुंबई नहीं छोड़ना चाहता हूं और वे मुझे बॉम्बे हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस बनाने को तैयार नहीं हैं।

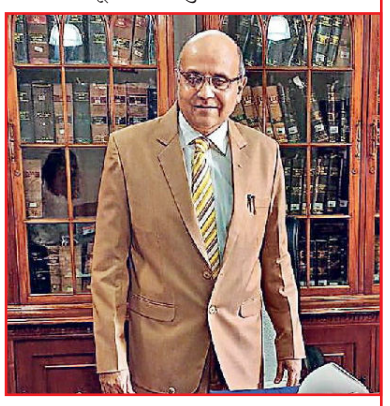

राष्ट्रपति को भेजा इस्तीफा

इससे पहले हाईकोर्ट में जस्टिस धर्माधिकारी ने वकील मैथ्यू नेदमपारा को अपने इस्तीफे की जानकारी तब दी, जब उन्होंने एक याचिका की सुनवाई के लिए अगले हफ्ते की तारीख मांगी।

जस्टिस धर्माधिकारी ने कहा, मैंने इस्तीफा दे दिया है, आज यहां मेरा अंतिम दिन है। उन्होंने गुरुवार शाम को ही अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज दिया है।

2003 में बॉम्बे हाईकोर्ट के जज बने थे

जस्टिस धर्माधिकारी 14 नवंबर 2003 को बॉम्बे हाईकोर्ट के जज बने थे। वह 2022 में सेवानिवृत्त होते। पिछले साल सितंबर में मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस वीके ताहिलरमानी ने इस्तीफा दे दिया था। वह सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के उस निर्णय से नाराज थी, जिसमें उनका तबादला मेघालय हाईकोर्ट में कर दिया गया था।

पेट्रोल लेकर मां-बेटी को जिंदा जलाने जा रहा युवक गिरफ्तार, शादी टूटने से था नाराज

पालघर। मुंबई से सटे पालघर जिले में एक युवक को पेट्रोल के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है युवक पेट्रोल लेकर एक महिला और उसकी बेटी को जिंदा आग के हवाले करने जा रहा था। युवक अपनी शादी टूटने से नाराज था। महिला ने अपनी बेटी की शादी युवक से कराने से इंकार कर दिया था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दशरथ पाटिल ने बताया आरोपी का नाम भैरो सिंह राठौड़ है। वह राजस्थान के अजमेर का रहने वाला है। कुछ महीने पहले राठौड़ और पीड़ित की लड़की के बीच शादी तय हुई थी। राठौड़ बेरोजगार

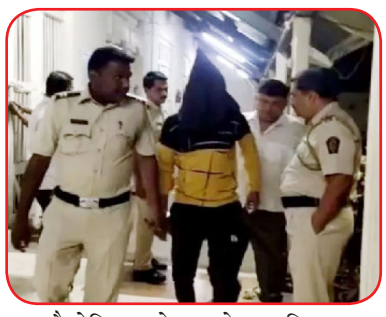

है लेकिन उसने झूठ बोलकर रिश्ता किया था। यह बात जब लड़की की मां को पता चली तो उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि इसके बाद राठौड़ ने लड़की को लेकर सोशल मीडिया में कई भद्दे कमेंट किए। परेशान होकर लड़की के परिजन ने पालघर पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। आरोपी ने लड़की के परिजन को धमकी दी थी कि उन्हें इसका बेहद बुरा अंजाम भुगतना होगा। शुक्रवार को वह पेट्रोल भरी बोतल लेकर लड़की के घर की ओर जा रहा था, तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

लेक सिटी मॉल के पहले फ्लोर पर लगी आग, बडी मुश्किल से पाया गया काबू

ठाणे। लेक सिटी मॉल की पहली पहली मंजिल पर आग लगी पर लगभग काबू कर लिया गया है। मौके पर दमकल की पांच गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची हुई थी। पूरे मॉल में धुंआ फैल जाने के कारण उसके बाहर लगे कांच तोड़कर धुंआ निकालना पड़ा।

यह मॉल कपूरवाड़ी में बालकुम फायर स्टेशन के ठीक पास है। इसलिए आग लगने की जानकारी मिलते ही मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची।

(पृष्ठ 1 का शेष)

आप की सरकार

दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री का आशीर्वाद चाहता हूं। आम आदमी पार्टी ने शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़कर किसी अन्य नेता को न्योता नहीं दिया। हालांकि, बनारस दौरे के चलते मोदी इसमें शामिल नहीं हो पाए। केजरीवाल ने अपने भाषण में इसका जिक्र भी किया। आप ने दिल्ली के विकास में योगदान देने वाली 50 लोगों को समारोह में विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया। शपथ लेने के बाद केजरीवाल ने कहा, आज आपके बेटे ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ये मेरी नहीं आप लोगों की जीत है। हर दिल्लीवाले की जीत है। हर मां-बहन की जीत है। पिछले 5 सालों में हमारी कोशिश रही है कि दिल्ली के हर परिवार की जिंदगी में खुशहाली ला सकें। दिल्ली का तेजी के साथ विकास हो और अगले 5 साल भी यही कोशिश जारी रहेगी। चुनाव में कुछ लोगों ने आप, भाजपा और कांग्रेस को वोट दिया। लेकिन मैंने आज शपथ ली है तो सबका मुख्यमंत्री हूं। मैं भाजपा और कांग्रेस वालों का भी सीएम हूं। 5 साल में कभी किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया। दिल्ली के दो करोड़ परिवारों से कहना चाहता हूं कि चुनाव अब खत्म हुआ। सभी 2 करोड़ लोग मेरे परिवार का हिस्सा हैं। बिना हिचक मेरे पास आ जाना, सबका काम करूंगा। चाहे किसी भी धर्म या जाति के हो। मैं सबके साथ मिलकर काम करना चाहता हूं। चुनाव में विरोधियों ने जो कहा मैंने सबको माफ कर दिया है। जो उठापटक हुई सब भूल जाओ। केंद्र के साथ मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री को भी शपथ ग्रहण का न्योता भेजा था। वे शायद व्यस्त हैं, इसलिए आ नहीं पाए। दिल्ली को आने बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री का भी आशीर्वाद चाहता हूं। केजरीवाल ने कहा, देशभर से खबर आ रही है कि कई सरकारों ने दिल्ली के मॉडल पर बिजली मुफ्त कर दी। मोहल्ला क्लीनिक शुरू कर दिए। कौन कहता है कि सरकारी स्कूल ठीक नहीं हो सकते। दिल्ली की तरफ देखो। आज मुझे खुशी है कि मेरे साथ यहां दिल्ली के निमार्ता मौजूद हैं।

देवेंद्र फडणवीस की चुनौती

मुंबई में बीजेपी के एक कार्यक्रम में बोलते हुए फडणवीस ने कहा, मैं शिवसेना को चुनौती देता हूं कि अगर आपमें इतना ही आत्मविश्वास है तो फिर से चुनाव लड़ लें। बीजेपी अकेले ही कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना को हरा देगी।' बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस-शिवसेना-एनसीपी तीन पार्टियों के गठबंधन में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसके साथ ही भीमा कोरेगांव की जांच का मामला एनआईए को सौंपे जाने पर एनसीपी और शिवसेना में हुई बयानबाजी पर फडणवीस ने कहा, 'भीमा कोरेगांव केस को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को ट्रांसफर किए जाने के लिए मैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को धन्यवाद देता हूं। शरद पवार इस कदम का विरोध कर रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कि एनआईए की जांच में सच सामने आ जाएगा।' इससे पहले उद्धव ठाकरे ने शिवसेना सरकार के द्वारा एनआईए को जांच सौंपे जाने का विरोध किया था। हालांकि बाद में वह पलट गए। गौरतलब है कि महाराष्ट्र की शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन वाली सरकार 'पल में तोला पल में माशा' वाले हाल पर चल रही है। तीनों पार्टियों के नेता कभी कुछ कहते हैं तो अगले ही पल पलट जाते हैं। इसका ताजा उदाहरण एनसीपी चीफ शरद पवार ने पेश किया है। एल्गार परिषद केस की जांच एनआईए को सौंपे जाने पर शरद पवार ने शुक्रवार को ही उद्धव ठाकरे को आड़े हाथ लिया था। अगले ही दिन शरद पवार ने शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे की तारीफ की है।

सीएए पर चर्चा के लिए शाह से मिलने...

सीएए पर आपत्ति जताने वाले लोग उनसे चर्चा करने आ सकते हैं। उन्होंने कहा था कि चर्चा के लिए तीन दिनों के भीतर समय दिया जाएगा। इससे पहले, शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने-बातचीत करने का न्योता दिया था। प्रदर्शनकारियों ने दिल के आकार के पोस्टरों पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाहीन बाग आएं, अपना गिफ्ट स्वीकार करें और हमसे बात करें। शाहीन बाग के ट्विटर हैंडल से भी प्रधानमंत्री को मिलने के लिए कहा गया है।

कांग्रेस नेता उदित राज बोले : देशभक्ति जनता को भरमाने का जरिया, लोग सत्ता के लिए 40 जवानों की जान का सौदा भी कर सकते हैं

☞ हाशिए पर खड़े समुदायों को सत्ताधारी सवर्णों की देशभक्ति की कीमत चुकानी पड़ती है: उदित राज

☞ राहुल गांधी ने शुक्रवार को 3 सवाल पूछे थे, कहा था- पुलवामा हमले से किसको फायदा हुआ

पुलवामा हमले की पहली बरसी के बाद कांग्रेस के नेता भाजपा सरकार को लगातार निशाना बना रहे हैं। शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हमले को लेकर तीन सवाल पूछे थे, तो वहीं अब शनिवार को उन्हीं की पार्टी के एक अन्य नेता उदित राज ने विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा, जो लोग सत्ता पाने के लिए गुजरात में नरसंहार करवा सकते हैं, वे सत्ता बनाए रखने के लिए 40 जवानों की जान का सौदा भी कर सकते हैं। इनके लिए देशभक्ति और राष्ट्रवाद जनता को भरमाने का एक टूल भर है।

उदित राज ने ट्वीट में आगे कहा, राहुल गांधी जी ने सही सवाल उठाया कि पुलवामा हमले के जांच का नतीजा अभी तक नही आया। जब गृह मंत्रालय को खबर मिल गई थी कि सीआरपीएफ को रोड से नहीं, बल्कि एयर से ले जाना चाहिए तो इजाजत नहीं दी अर्थात राजनैतिक लाभ के लिए यह घटना होने दिया। जो लोग सत्ता पाने के लिये गुजरात में नरसंहार करवा सकते हैं, वो सत्ता बनाये रखने के लिये 40 जवानों की जान का सौदा भी कर सकते हैं। इनके लिये देशभक्ति और राष्ट्रवाद जनता को भरमाने का एक टूल भर है। राष्ट्रवाद का प्रचार करने वाले लोग अक्सर उच्च जाति के होते हैं और जिन लोग अक्सर उच्च जाति के होते हैं उन्होंने आगे लिखा, सोशल मीडिया पर राष्ट्रवाद का प्रचार करने वाले सैनिकों ने मुख्य रूप से हमले में अपनी जान गंवाई वे एससी/एसटी/ओबीसी समुदायों से आते हैं। हाशिए पर खड़े समुदायों को सत्ताधारी सवर्णों की देशभक्ति की कीमत चुकानी पड़ती है। विद्रोहियों और सुरक्षाबलों की लड़ाई में क्यों मरते हैं सिर्फ हाशिए के लोग। पुलवामा और दंतेवाड़ा जैसे हिंसक हमलों में मरने वाले लोग मुख्यरूप से दलित, आदिवासी या ओबीसी समुदायों से होते हैं। राहुल ने पूछा- हमले के बाद हुई जांच का परिणाम क्या निकला। इससे पहले राहुल ने हमले को लेकर तीन सवाल पूछे थे। पहला, इस हमले से सबसे ज्यादा किसे फायदा मिला? दूसरा, हमले के बाद हुई जांच का परिणाम क्या निकला और तीसरा, भाजपा सरकार ने इस हमले को लेकर हुई चूक के लिए किसे जिम्मेदार ठहराई है?

राजनीति में अधराधियों की संख्या लगातार बढ़ती रोक जरुरी

उल्लेखनीय है कि राजनीति में अधराधियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 2004 में जहां 24 प्रतिशत आपराधिक पृष्ठभूमि के सांसद थे, वह संख्या 2009 में 30 प्रतिशत और 2014 में बढ़ कर 34 प्रतिशत हो गई इन आंकड़ों के बावजूद 2019 में यह संख्या 30 प्रतिशत के लगभग रही। ऐसे नेताओं को संसदीय लोकतंत्र से दूर रखने की जिम्मेवारी संसद की है, मगर जमीनी हकीकत यह है कि राजनीतिक दलों पर इनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि उनके बिना सत्ता और चुनाव की राजनीति संभव नहीं। सच है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के, आवारा पूंजी,धर्म और अपराध के विषवृक्ष कैसे फलते-फूलते! महंगे चुनावों का आर्थिक बोझ कौन उठाएगा! बाहुबली जो पहले नेताओं का पीछे से समर्थन करते थे, बाद में खुद राजनेता बन कर उभरने लगे। साम्प्रदायिक राजनीति के दौर में मंदिर-मस्जिद और मठों की भूमिका भी, निरंतर निर्णायक होती चली गई। वस्तुस्थिति यह भी है कि सब कुछ जानते हुए भी मतदाताओं ने आपराधिक छवि वाले नेताओं को भी, भारी बहुमत से जीतने दिया है। धनबल, बाहुबल के अलावा सामंती संस्कार और जातीय वर्चस्व के सामने मतदाता अभी भी कितना कमजोर और असहाय है, महानगरों के वातानुकूलित ड्राइंग रूम में बैठ कर इसका अनुमान तक लगाना मुश्किल है। अनपढ़, गरीब-ग्रामीण क्या करे, किससे कहें। पिछले तीस-चालीस सालों में प्रमुख राजनीतिक दलों और ज्यादातर धार्मिक संस्थाओं (बाबा,गुरु,संत, महंत, स्वामी) के पास हजारों करोड़ की संपत्ति जमा हो गई है। कारण- धार्मिक संस्थाओं और राजनीतिक दलों को आयकर से पूरी छूट। इन्हें दान देने वालों को, दान के पचास प्रतिशत पर आयकर से छूट। अक्सर कालाधन भी रातों-रात सफेद। धीरे-धीरे अधिकांश धार्मिक संस्थाओं में व्यवसायीकरण और राजनीतीकरण के साथ-साथ अपराधीकरण भी बढ़ता गया। सिद्ध-प्रसिद्ध धार्मिक बाबा,गुरु,संत, महंत, स्वामी और धमाचार्यों के सामने, बहुत से मंत्री-मुख्यमंत्री और अफसर चरण वंदना करते पाये गये, सो सत्ता संरक्षण के अलावा समाज में इनका मान-सम्मान भी बढ़ा और भारतीय मध्यम वर्ग की अंधभक्ति या अटूट आस्था-विश्वास भी। देखते-देखते राजनीति में धमाचार्यों का हस्तक्षेप और राजनेताओं द्वारा चुनाव की राजनीति में धर्म का इस्तेमाल भी बढ़ता गया। परिणामस्वरूप

अशोक भाटिया

अशिक्षित, निर्धन, दलित और असहाय आम जनता का हर तरह से शोषण और उत्पीड़न लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में हर पांचवे साल बिछती है चुनाव की चौपड़ और 'नोट के बदले वोट' में देखते ही देखते नीलाम हो जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र-प्रजातंत्र। आपराधिक मामलों का सामना कर रहे नेताओं को उम्मीदवार बनाने के मामले में उच्चतम न्यायलय ने जो दिशा-निर्देश दिए वे स्वागतयोग्य तो हैं, लेकिन इसमें संदेह है कि उनसे बात बनेगी और विधान मंडलों में दागी छवि वाले नेताओं के प्रवेश का सिलसिला थमेगा। इसका कारण यह है कि राजनीतिक दल दागी नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने के लिए ऐसे तर्कों की आड़ ले सकते हैं कि उनके खिलाफ चल रहे मामले राजनीतिक बदले की कार्रवाई का नतीजा हैं। इसके अलावा उनके पास यह सदाबहार आड़ तो है ही कि दोष सिद्ध न होने तक हर किसी को निर्दोष माना जाना चाहिए और वे भी ऐसा ही मानते हैं राजनीतिक दलों की ओर से यह भी कहा जा सकता है कि वे आपराधिक छवि एवं अतीत वाले व्यक्ति को सुधरने का मौका दे रहे हैं। आखिर यह एक तथ्य है कि एक समय कई दलों ने छंटे हुए बाहुबलियों को यह कहकर चुनाव मैदान में उतारा कि वे उन्हें सही रास्ते पर चलने का मौका दे रहे हैं। यदि नामांकन पत्र में आपराधिक मामलों का विवरण देने से दागी प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने और जीतने के सिलसिले में कमी नहीं आई तो फिर यह उम्मीद कैसे की जा सकती है कि ऐसा विवरण मीडिया और सोशल मीडिया में सार्वजनिक करने से आम जनता उन्हें वोट देने से कतराएगी? क्या यह किसी से छिपा है कि तमाम प्रत्याशी जाति, मजहब, क्षेत्र आदि के आधार पर जन समर्थन हासिल कर लेते हैं?

दागी लोगों को संसद और विधानसभाओं से दूर रखने का उचित उपाय तो यही है कि उन्हें चुनाव लड़ने की सुविधा ही न दी जाए। निर्वाचन आयोग एक अर्से से यह कह रहा है कि उन लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जाए जिनके खिलाफ ऐसे संगीन मामले चल रहे हों जिनमें पांच साल से अधिक की सजा हो सकती है और जिनमें आरोप पत्र भी दायर हो चुका हो। अच्छा होता कि सुप्रीम कोर्ट इस उपाय को अपने दिशा-निर्देशों का हिस्सा बनाता या फिर चुनाव आयोग को यह अधिकार देता कि वह राजनीतिक दलों की उन कमजोर दलीलों को ठुकरा सकता है जो वे किसी दागी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाने के मामले में दें।जब राजनीति के अपराधीकरण की समस्या विकराल रूप ले चुकी हो और उसका दुष्प्रभाव बढ़ता चला जा रहा हो तो तब कुछ कठोर एवं कारगर उपायों पर अमल समय की मांग है। यह मांग पूरी होनी ही चाहिए। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि दागी जनप्रतिनिधियों की बढ़ती संख्या न्यायपालिका की सुस्ती का भी दुष्परिणाम है। बेहतर हो कि उच्चतम न्यायलय इस सुस्ती को दूर करने के लिए भी सक्रियता दिखाए।

एयरपोर्ट से उड़ान भरने जा रहे एयर इंडिया के विमान के सामने जीप आई, पायलट ने तुरंत टेकऑफ कर बड़ा हादसा टाला

पुणे एयरपोर्ट पर शनिवार को एयर इंडिया का एक विमान दुर्घटना से बाल-बाल बच गया। डीजीसीए ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि एयरपोर्ट के रनवे पर जैसे ही विमान उड़ान भरने के लिए तैयार हुआ, वैसे ही उसके सामने जीप और एक व्यक्ति आ गया। इस दौरान विमान की रफ्तार 222 किमी/घंटा (120 नॉट्स) थी। हालांकि, पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए विमान को रन पूरा होने से पहले ही टेकऑफ करा लिया। इस दौरान विमान का फ्यूल टैंक क्षतिग्रस्त हुआ। हालांकि, प्लेन को बीच में कहीं इमरजेंसी लैंडिंग नहीं करनी पड़ी और वह सुरक्षित दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। डीजीसीए ने एयर इंडिया को सलाह दी है कि वह प्लेन से कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर (सीवीआर) को सुरक्षित निकाल ले, ताकि इसका विश्लेषण किया जा सके। हादसे की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने बताया कि प्लेन को जांच के लिए सेवा से हटा लिया गया है।

एयर इंडिया को पुणे एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) के साथ मिलकर घटना की जांच में शामिल होने और रनवे पर मार्किंग का पता लगाने के लिए कहा गया है। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा, ए321 विमान के पिछले हिस्से में रगड़ के कुछ दाग देखे गए। फिलहाल विमान को जांच के लिए सेवा से हटाया गया है। इसके फ्लाइट रिकॉर्ड डेटा की बेहतर ढंग से जांच होगी और फिर जो भी जानकारी सामने आएगी, उसे सार्वजनिक किया जाएगा।

कश्मीर पर तुर्की के राष्ट्रपति के बयान पर भारत ने कहा- हमारे अंदरूनी मामले में दखल न दें

अर्दोआन ने पाकिस्तानी संसद में कहा था- कश्मीर पाकिस्तान के लिए जितना महत्वपूर्ण है, हमारे लिए भी उतना ही अहम

भारत ने शनिवार को कश्मीर पर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन के सभी बयानों को खारिज किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। बेहतर होगा कि अर्दोआन भारत के अंदरूनी मामलों में दखल न दें और अपने तथ्यों की जानकारी बढ़ाएं। उन्हें पाकिस्तान से चलने वाले आतंकवाद से भारत समेत अन्य देशों पर बढ़ रहे खतरे के बारे में सोचना चाहिए।

तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन ने शुक्रवार को पाकिस्तान में संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान के लिए जितना महत्वपूर्ण है, उनके देश के लिए भी उतना ही अहम है।

अर्दोआन ने पाकिस्तानी संसद में कहा था,तुर्की की आजादी की लड़ाई के समय पाकिस्तान के लोगों ने अपनी हिस्से की रोटी हमें दी थी। पाकिस्तान की इस मदद को हम नहीं भूले हैं और न कभी भूलेंगे। कल हमारे लिए जैसे कनक्कल (तुर्की का समुद्र

तटीय हिस्सा) अहम था, बिलकुल उसी तरह आज कश्मीर हमारे लिए मायने रखता है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। पिछले कुछ सालों में एकतरफा कार्रवाई से कश्मीरी लोगों की तकलीफों में इजाफा हुआ है। हम कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ जारी रखेंगे।

अर्दोआन ने सितंबर में संयुक्त राष्ट्र में भी भी कश्मीर का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन करने का दावा किया था। अर्दोआन ने कहा था कि भारतीय कश्मीर में 80 लाख लोग फंसे हुए हैं। दक्षिण एशिया की स्थिरता को कश्मीर से अलग नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि कश्मीर का मुद्दा 72 साल पुराना है। इसे न्याय और निष्पक्षता के आधार पर बातचीत के जरिए हल किया जाए। उन्होंने कश्मीर संघर्ष पर ध्यान देने में विफल रहने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय की आलोचना की थी।

कोरोना वायरस : जापानी क्रूज पर किसी भी भारतीय में संक्रमण नहीं, चीन में मृतकों की संख्या 1600 पार,

67 हजार से ज्यादा संक्रमित

- चीन में कोरोनावायरस पर नियंत्रण और निगरानी के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है
- जापान के योकोहामा पोर्ट पर खड़े क्रूज में 3 भारतीय समेत 218 लोग वायरस से संक्रमित पाए गए थे

जापान के योकोहामा बंदरगाह पर खड़े डायमंड प्रिंसेज क्रूज शिप में अब कोई भी भारतीय कोरोनावायरस से संक्रमित नहीं है। जापान स्थित भारतीय दूतावास ने शनिवार को कहा, 'यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कोविड-19 से संक्रमित 3 भारतीयों की स्थिति प्रांत में अब सुधार हो रहा है और जापानी क्रूज पर अब कोई भी भारतीय इस वायरस से संक्रमित नहीं है।' इस महीने की शुरूआत में जापानी तट पर पहुंचे क्रूज में 138 भारतीय समेत 3711 लोग मौजूद थे। भारतीयों में 132 क्रू मेंबर्स और 6 यात्री शामिल थे। जहाज में 3 भारतीय समेत 218 लोग कोविड-19 वायरस से संक्रमित पाए गए थे। वहीं, आईटीबीपी ने जानकारी दी है कि उसके छावला स्थित सेंटर पर रोके गए सभी 406 लोग स्वस्थ हैं। इनके अंतिम नमूने ले लिए गए हैं, अगर वह रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो इन्हें अगले हफ्ते घर भेज दिया जाएगा।

वहीं, चीन में कोरोनावायरस से अब तक 1631 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 67,535 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक, शुक्रवार को सिर्फ हुबेई प्रांत में 2420 नए संक्रमित मामले पाए गए। पिछले 24 घंटे में चीन में 143 लोगों की मौत हो गई। अकेले हुबेई प्रांत में 139 लोगों की मौत हुई। चीन के 31 प्रांत कोरोनावायरस से प्रभावित हैं। हुबेई प्रांत में अब तक 54 हजार 406 मामलों की पुष्टि हुई है। मृतकों और संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए गृह मंत्रालय ने नेपाल, भूटान और चीन के बॉर्डर पर तैनात आईटीबीपी और एसएसबी जवानों को ज्यादा सावधानी बरतने के लिए कहा है। मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा था कि बॉर्डर चेकपॉइंट पर भी संदिग्धों की जांच के लिए एयरपोर्ट जैसी सुरक्षा रखें। वहीं, डीजीसीए ने एयरपोर्ट प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वे चीन के अलावा जापान और दक्षिण कोरिया से आने वाले यात्रियों की भी जांच शुरू करें।

शुक्रवार को चीनी अधिकारी ने बताया कि हुबेई को छोड़कर देश के अन्य हिस्सों में कोरोनावायरस के मामलों में कमी आई है। हालांकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बताया कि वायरस की रोकथाम और निगरानी रखने के लिए बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कम्प्यूटिंग के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। संक्रमित मरीजों को दवाइयां और अन्य सुविधाओं की आपूर्ति के लिए अस्पतालों में रोबोट को तैनात किया गया है। चीन से बाहर 580 नए मामले पाए गए हैं। फिलीपींस और हॉन्गकॉन्ग में एक-एक जबकि जापान में 80 साल की एक महिला संक्रमित पाई गईं। महामारी से निपटने के लिए चीन को 30 देशों और चार अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने मेडिकल संबंधी मदद दी। वहीं, टेक दिग्गज अलीबाबा ने भी इसकी दवा विकसित करने के लिए 1022 करोड़ रु. की मदद दी है।

चीन में 1700 स्वास्थ्यकर्मी वायरस की चपेट में है। इनमें 6 स्वास्थ्यकर्मियों की मौत हो गई। अस्पतालों में डॉक्टर बिना मास्क और सुरक्षा उपकरणों के बिना वहां दिन-रात जुटे हैं। वहीं, डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि उसकी टीम के पूरे सदस्य हफ्ते के अंत तक चीन पहुंच जाएंगे। एक टीम पहले ही पहुंच चुकी है। इस टीम में दुनियाभर के 10 विशेषज्ञ हैं। यह टीम बीमारी रोकने के उपाय खोजेगी। कोरोनावायरस की महामारी से लड़ने के लिए वुहान के लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए अमेरिका, ताइवान, फिलीपींस में लूनर न्यू ईयर परेड हुई। इसमें लोग 'वुहान स्टे स्ट्रॉन्ग', 'लॉन्ग लिव वुहान' जैसे संदेश लिखी तख्तियां और पोस्टर निकले। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कोरोनावायरस को लेकर गलत जानकारियों पर लगाम लगाने के लिए फेसबुक, अमेजन और गूगल जैसी टेक कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की है। प्रसारणकर्ता यूएस सीएनबीसी के मुताबिक यह बैठक फेसबुक के कैलिफोर्निया स्थित मुख्यालय में हुई। डब्ल्यूएचओ के प्रतिनिधि एंडी पैटिंसन ने कहा, 'इस बैठक का उद्देश्य अफवाहों को रोकने पर विचार सामने लाना और उन्हें सही तरीके से कार्यान्वित करना है। मैं विभिन्न कंपनियों के बीच सहयोग और उनके तरीके को प्रोत्साहित करता हूं। संकट की इस घड़ी में यह उचित समय है।' पैटिंसन ने कंपनियों से कहा कि वे खुद या उनके यूजर द्वारा प्रकाशित किसी भी तरह की जानकारियों का तथ्य प्रमाणित करने पर जोर दें।

संगरुर में स्कूल वैन में आग लगी, 4 बच्चों की जलकर मौत

एक स्कूल वैन में आग गई। हादसे में 4 बच्चों की जिंदा जलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वैन में 12 बच्चे सवार थे। 8 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जबकि 10 से 12 साल के चार बच्चे वैन में फंस गए। उनकी जलकर मौत हो गई। हादसा लौंगोवाल इलाके में हुआ।

पुलिस ने बताया कि सिमरन पब्लिक स्कूल की मारुति वैन बच्चों को घर छोड़ने लौंगोवाल की तरफ जा रही थी। रास्ते में गांव केहर सिंह वाली के पास वैन में अचानक आग लग गई। वैन में तैनात स्टाफ ने बच्चों को निकालना शुरू किया, लेकिन देखते-देखते तेजी से फैली आग ने पूरी वैन को चपेट में ले लिया। इसमें फंसे 4 बच्चों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। हादसे में ड्राइवर जख्मी है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मोरबी में 30 बेशकीमती कारों में 200 गरीब बच्चों को घुमाया गया, बच्चे भावविभोर

हमारे करीब से कोई महंगी कार फरार्टे से निकल जाए, तो हम सोचने लगते हैं कि काश, हम भी ऐसी कार में बैठकर घूम सकते। आम आदमी के लिए भले ही यह एक सपना हो, जो कभी न कभी पूरा हो ही जाता है। पर उन गरीब बच्चों का क्या, जिनके पास रहने को घर तक नहीं। ऐसे बच्चों को यदि ऐसी ही बेशकीमती कारों में घूमने का मौका मिल जाए, तो सोचो, कितना अच्छा लगा होगा उन्हें। बच्चों के इस सपने को वेलेंटाइन डे पर यंग इंडिया ग्रुप ने पूरा किया।

वेलेंटाइन डे को अनोखे रूप में मनाने का संकल्प किया, यहां की सेवाभावी संस्था यंग इंडिया ग्रुप ने। संस्था ने 30 लक्जीरियस कारों की व्यवस्था कर झोपड़पट्टी के 200 बच्चों को दिन-भर घुमाया। फिर सभी को होटल में खाना खिलाया। बच्चों के लिए मानो, यह एक सपना था, जो वेलेंटाइन डे पर पूरा हुआ। महंगी कारों में बैठकर बच्चे चहक रहे थे। उनकी खुशी का पारावार नहीं था।

सिर्फ 7,000 में करें खूबसूरत वायनाड की सैर, जानें टूर पैकेज के डीटेल्स

केरल को 'गॉड्स ओन कंट्री' कहा जाता है। यहां देश और दुनियाभर से पर्यटक घूमने के लिए पहुंचते हैं। केरल में घूमने को काफी कुछ है लेकिन इसमें भी वायनाड की बात सबसे अलग है। पहाड़ों, टी-एस्टेट, कॉफी प्लान्टेशन की वजह से यह जगह और भी खूबसूरत बन जाती है। अगर आप भी वायनाड घूमना चाहते हैं, तो इंडियन रेलवे कैटरिंग ऐंड टूरिजम कॉर्पोरेशन (आईआरसीटीसी) आपके लिए एक बेहतरीन टूर पैकेज लेकर आया है। तीन रात और चार दिनों के इस टूर का नाम वंडरफुल वायनाड फ्रॉम चेन्नै है।

आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, इस टूर पैकेज में यात्रियों को स्लिपर क्लास में चेन्नै से वायनाड तक का सफर तय करना होगा। इसके अलावा स्लिपर क्लास से ही वापसी, वायनाड में 2 नाइट एसी आवास में स्टे, एसी वाहन द्वारा सड़क परिवहन की सुविधा दी जाएगी। साथ ही कार्यक्रम के अनुसार सभी दर्शनीय स्थलों का भ्रमण और यात्रा बीमा टूर पैकेज में शामिल ही। 30 जनवरी 2020 से प्रत्येक गुरुवार को ट्रेन चेन्नै रेलवे स्टेशन से शाम पांच बजे खुलेगी।

इस टूर पर आपको पझासी राजा मकबरा, कुरुवा द्वीप, तिरुनेली मंदिर, बाणासुर सागर बांध, मुथांगा वन्यजीव अभयारण्य, अंबालावयाल हैरिटेज म्यूजियम, एडाक्कल गुफाएं, सूचिपारा झरना, पुक्कोड झील, लक्कीडी व्यू पाइंट, तुशागिरी झरना जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन्स की सैर करने का मौका मिलेगा। बात करें टूर पैकेज के किराये की, तो ट्विन शेयरिंग के लिए आपको प्रति व्यक्ति 7, 330 रुपये बतौर किराया खर्च करना होगा। वहीं ट्रिपल शेयरिंग के लिए आपको प्रति व्यक्ति 6,830 रुपये खर्च करने होंगे। अगर आपके साथ बच्चे हैं, तो बगैर बेड के आपको प्रति व्यक्ति 5,100 रुपये और बेड लेने पर प्रति व्यक्ति 6, 210 रुपये खर्च करने होंगे।

ताकि बच्चा मातृभूमि की मिट्टी पर रखे पहला कदम, पिता ने खर्च किए 200 डॉलर

आमतौर पर हम सभी को अपनी जन्मभूमि से बेहद प्यार होता है। यहां की म्टिटी से एक अलग ही लगाव होता है। पढ़ाई और नौकरी के लिए भले ही हम कितने ही दूर क्यों न चलें जाएं लेकिन जन्मभूमि के लिए प्रेम कभी कम नहीं होता। ऐसा ही कुछ दीवानगी सात समंदर पार अमेरिका में भी देखने को मिली है। यहां एक शख्स की मिट्टी के प्रति दीवानगी ये है कि उन्होंने अपने बच्चे के पहले कदम के लिए बकायदा अपनी मृातभूमि की मिट्टी खरीदकर मंगवाई। इसके लिए उन्होंने 200 डालर रुपये खर्च किए। टोनी ट्रेकोनी अमेरिका के प्रांत टेक्सास में रहते हैं। यहीं उनका जन्म हुआ और आगे की पढ़ाई-लिखाई भी सब यहीं हुई। वे पेशे से सेना के जवान हैं। टोनी ट्रेकोनी चाहते थे कि जब भी उनके बच्चे का जन्म हो, तो वह अमेरिका यानी उनकी मातृभूमि पर ही हो। लेकिन जब वाइफ प्रेग्नेंट हुई तब उनकी पोस्टिंग इटली के प्रांत पडुआ में हो गई। उन्हें उम्मीद थी कि डिलीवरी तक वह अपने देश लौट जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वे अपने देश की मिट्टी खरीदकर मंगवाई। टोनी ने डिलीवरी से एक महीना पहले अपने प्रांत टेक्सास की मिट्टी इटली मंगवाई। ताकि जब उनका बच्चा इस दुनिया में आए तो वह पहला कदम उसी मिट्टी पर रखे, जहां उसके माता-पिता जन्मे और पले-बढ़े हैं। इसके लिए उन्होंने टेक्सास में अपने पैरेंट्स से कहा कि वह एक कंटेनर में मिट्टी भरकर शिप के जरिए इटली भेज दें। उनके पैरेंट्स ने ये किया भी। इसके लिए उन्हें 200 डॉलर (लगभग 14 हजार रुपये) खर्च करने पड़े।

मुंबई हलचल राशिफल

आचार्य परमानंद शास्त्री

मेष
अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करें। लेटलतीफी कार्यालय में भारी पड़ सकती है। किसी से पैसों के लेनदेन में सावधानी बरतें।

सिंह
नौकरी में पदोन्नति के साथ स्थानांतर के योग बन रहे हैं। नए दायित्व को लेकर खुशी मिल सकती है। कोई पुरानी बीमारी अचानक उभर सकती है।

धनु
कार्यालय में कुछ परेशानी आ सकती है। आपकी लापरवाही से अधिकारी के आक्रोश का शिकार हो सकते हैं। अपने दायित्व को ठीक तरह से निभाएं।

वृष
मौसम की प्रतिकूलता स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है इसलिये सचेत रहें। व्यापार में नुकसान उठाना पड़ सकता है। धार्मिक आयोजनों में सक्रियता से हिस्सा लेंगे।

कन्या
कहीं से नौकरी को लेकर आकर्षक प्रस्ताव सामने आ सकता है लेकिन अपने विवेक से सोच समझकर ही निर्णय लें। व्यापार में लाभ के अवसर मिल रहे हैं।

मकर
आपका मनमाना रवैया दूसरों को परेशानी में डाल सकता है। काम में लापरवाही भारी पड़ सकती है। मौसम का परिवर्तन स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है।

मिथुन
कोई आपको बरगलाने का प्रयास कर सकता है इसलिये सावधान रहें। आर्थिक मसलों को पारदर्शिता से निपटाएं। व्यापार में लाभ की संभावना है।

तुला
मेहमानों के आगमन से घर में खुशी का माहौल रहेगा। कोई अपना ही आपको भ्रमित कर सकता है इसलिये सतर्क रहें। बुजुर्गों के मार्गदर्शन को महत्व दें।

कुंभ
परिवार के लोगों के साथ धार्मिक यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। यात्रा के दौरान चोरी, दुर्घटना का भय भी है। बच्चों के शैक्षणिक भविष्य की चिंता परेशान कर सकती है।

कर्क
कोई अनचाहा कार्य आपको परेशानी में डाल सकता है। अपने कार्य के प्रति लापरवाही ठीक नहीं है। स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेंगे।

वृश्चिक
अविवाहितों को विवाह के मौके मिल सकते हैं। परिवार में खुशी का क्षण उपस्थित हो सकता है। मौसमी बीमारियों से कुछ परेशानी हो सकती है।

मीन
दिन शुभ रहेगा। आपकी सक्रियता और कार्यशैली लोगों के बीच चर्चा का विषय बन सकती है। अभी कहीं यात्रा का कार्यक्रम बनाने से बचें क्योंकि समय अनुकूल नहीं है।

छोटे बच्चे के साथ सफर पर जा रहे हैं, तो इन बातों का रखें ध्यान

परिवार के साथ छुट्टियां, यह वाक्य सुनने में ही कितना अच्छा लगता है। बात जब बच्चों के साथ सफर की आती है, तो हमें खास सावधानी बरतनी पड़ती है क्योंकि बच्चे की जरूरतें आप से अलग होती हैं। बच्चों के साथ घूमने जाना भी मजेदार होता है, क्योंकि आप उनके साथ काफी समय स्पेंड कर पाते हैं। लेकिन अगर बच्चा बहुत छोटा है तो पैकिंग करते समय आपको कुछ बातों को खासतौर पर ध्यान में रखना जरूरी है। अगर आप इन बातों का ध्यान रख लें, तो आपका सफर मजेदार बन सकता है।

रुक-रुक कर करें सफर

मॉम स्प्रेसो की एक्सपर्ट सविता चौधरी बताती हैं कि अगर आप कार से जा रहे हैं, तो बीच-बीच में रुकते जाएं। इससे बच्चा फ्रेश रहेगा। साथ ही, उसे लगातार बैठे रहने से चिढ़ भी नहीं होगी। ऐसी जगहों पर ही गाड़ी रोकें, जो बच्चों के लिहाज से सही और सुरक्षित हों।

रात में रुकना हो तो

अगर आपका रात में कहीं रुकने का प्लान है, तो अंधेरा होने से पहले ही होटल में पहुंच जाएं। इससे बच्चे को जिन चीजों की जरूरत होगी, वह आप मंगवा सकती हैं। वैसे, भी बच्चे को सफर के बाद पर्याप्त आराम की जरूरत होती है। अगर वह नहीं मिलेगा, तो अगले पूरे दिन वह चिड़चिड़ा रहेगा।

फीडिंग

बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर बच्चा बोतल का दूध लेता है, तो ग्लास बॉटल लेकर चलें। इसे क्लीन रखना आसान है और यह प्लास्टिक के मुकाबले काफी ज्यादा समय तक चलती है। इसे बैक्टीरिया फ्री रखने में भी ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती।

बच्चों के कई जोड़ी कपड़ें लेकर चलें। हो सकता है आपको हर घंटे अपने शिशु की नैप्पी बदलनी पड़े, तो आपके पास कई नैप्पी होंगी, तो आप आराम से उनको चेंज कर पाएंगी। इससे बच्चे को स्किन एलर्जी व रैशेस भी नहीं आएंगे। आप जहां छुट्टियों पर जा रहे हैं, वह के मौसम का भी ध्यान रखें।

स्वच्छता

बच्चे के साथ ट्रैवल करते समय पैरेंट्स की सबसे बड़ी चिंता होती है कि उनके बच्चे को इन्फेक्शन न हो। इसलिए बच्चे को संभालते समय हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। एंटीसेप्टिक लिक्विड भी साथ में रखें।

कॉटन के कपड़े ही पहनाएं

यात्रा के दौरान बच्चे को सूती कपड़े ही पहनाएं। ज्यादा चुभने वाले कपड़े सही नहीं होते हैं, उससे बच्चे परेशान हो जाते हैं। बच्चा कम्फर्ट रहेगा, तभी आपका सफर भी आरामदायक हो पाएगा। बच्चों की जरुरत का हर सामान साथ में जरूर रखें।

दैनिक मुंबई हलचल
अब हर सच होगा उजागर

ब्यूटी के बहुत काम आएंगी घर में नजरअंदाज की जाने वाली ये चीजें

हर लड़की को ब्यूटी से जुड़ी कोई न कोई समस्या जरूर होती है। किसी एक समस्या को दूर करने के लिए वे इतनी परेशान होती है कि बाजार से ढेरों तरह के ब्यूटी प्रॉडक्टस खरीद लाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारी रसोई घर में बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जिनसे हम ढेरों तरह की सौदर्य से जुड़ी दिक्कतों को आसानी से दूर कर सकते हैं। जिसके लिए अलग से पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ते और किसी भी तरह का साइड इफैक्ट होने का डर भी नहीं रहता। आइए जानें आसानी से घर में मिलने वाली कौन सी चीजें हैं, जिसे आप नजरअंदाज कर रहे हैं।

1. टूथपेस्ट

हर कोई सुबह सबसे पहले लोग दांत साफ करने के लिए टूथपेस्ट का ही इस्तेमाल करते हैं लेकिन यह इसके अलावा भी और बहुत से काम आ सकता है। चेहरे पर मुंहासे हो गए हैं तो थोडा सा टूथपेस्ट लगा लें। यह पिंपल्स को खत्म कर देगा। इसके अलावा कांच का टेबल और दरवाजे साफ करने में भी ये बेहद कारगर है।

2. बासी लार

बासी लार किसी दवाई से कम नहीं है। सुबह उठते ही मुंह में आने वाली पहली लार को पिंपल्स पर लगा लें। इससे ये एक ही दिन में गायब हो जाएंगे और किसी भी तरह का कोई निशान भी नहीं पड़ेगा।

3. बेकिंग सोडा और नींबू

किचन में खाने के लिए इस्तेमाल होने वाला बेकिंग सोडा दांतों का पीलापन दूर करने में मददगार है। थोड़ा-सा बेकिंग सोडा लेकर इसमें नींबू का रस मिलाएं और इस पेस्ट से दांतों को साफ करें। इस बात का खास ध्यान रखें कि इसे हफ्ते में सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल करें और 30 सैकेंड से ज्यादा दांत साफ न करें।

4. प्याज

प्याज का रस बालों के लिए बेहद कारगर है। इससे बाल झड़ने का परेशानी से छुटकारा मिलता है। आप भी झड़ते बालों से टेंशन में रहते हैं तो इसके रस को निकाल कर बालों की जड़ों में लगाएं। फायदा मिलेगा।

5. क्रोसिन की गोली

जरा सा बुखार होने पर लोग क्रोसिन की गोली खाना सही समझते हैं लेकिन यह बालों में होने वाली रूसी को खत्म करने में भी बेहद कारगर है। इसमें पाया जाने वाला सिलीसिलिक एसिड बालों से डैड्रफ को पूरी तरह से हटा देता है। उसकी एक गोली को पीसकर अपने शैंपू में डालकर इससे बाल धोएं। इस बात का ध्यान रखें कि इसे 5 मिनट से ज्यादा अपने बालों पर लगा न रहने दें। इससे डैड्रफ से छुटकारा मिलेगा। इसका इस्तेमाल हफ्ते में एक बार ही करें। किसी तरह की इंफैक्शन होने पर इसका इस्तेमाव तुरंत बंद कर दें।

करीना की तरह Cheek bones पाने के लिए ट्राई करें ये 3 तीन स्टेप

करीना कपूर के परफैक्ट मेकअप का हर कोई दिवाना है। रेड कारपेट हो, फैमिली फंक्शन या एयरपोर्ट लुक वह हर समय बेहद खूबसूरत लगती हैं। परफैक्ट चीक बोन्स इस पौधे से बालों की हर छोटी से बड़ी समस्या दूर हो जाती है। बाल छड गए हैं तो एलोविरा जैल को नियमित रूप से बालो में लगाते रहने से नए बाल उगने लगते हैं। आइए जानें कौन-कौन से हैं इसके फायदे।

एलोविरा के साथ तेजी से लंबे करें बाल

बालों का झडना बंद

रोजाना कंघी करते समय थोड़े से बाल झडना आम बात है लेकिन बाल टूट कर ज्यादा गिर रहे हैं तो तुरंत एलोविरा का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अपने शैंपू में दोगुनी मात्रा में एलोविरा का ताजा जैल मिलाकर बाल धोएं। इससे बालों को विटामिन और मिनरल्स समेत पूरा पोषण मिलेगा और यह मजबूत होने शुरू हो जाएंगे।

घने और चमकदार बाल

घने और चमकदार बालों की चाहत रखते हैं तो एलोविरा आपके लिए बैस्ट है। इसके लिए एलोविरा जैल, थोड़ा सा नारियल का तेल, दूध और शैंपू को अच्छे से मिला लें। हफ्ते में दो बार इस शैंपू से बाल धोएं। कुछ ही दिनों में बालों में चमक आनी शुरू हो जाएगी।

चिपचिपाहट करें दूर

बाल धोने के बाद भी चिपचिपे नजर आते हैं तो एलोविरा जैल बिना रूखेपन के आपकी ये परेशानी दूर कर देगा। ताजे एलोविरा जैल को पत्ते से निकाल पर मिक्सी में पीस लें। अब इसे बालों की जड़ें में तेल की तरह आधे घंटे के लिए लगाएं। इसके बाद शैंपू से बाल धोएं।

बालों का झडना, रूखापन, असमय सफेदी, रूसी और न जाने कौन-कौन सी समस्याएं आजकल आम सुनने को मिलती हैं। इन सबके पीछे का कारण बालों की सही तरह से देखभाल न करना, मंहगे लेकिन कैमिक्ल युक्त प्रॉडक्ट्स का इस्तेमाल, बालों पर किए जाने वाले जरूरत से ज्यादा एक्सपेरिमेंट, खान-पान में गड़बड़ी, प्रदूषण के अलावा और भी बहुत से कारण हैं। जिससे लड़कियां तो क्या लड़के भी परेशान रहते हैं लेकिन बालों से जुड़ी हर समस्या के लिए वरदान है एलोविरा। यह एक औषधिय पौधा है, जिसे ग्वारपाठा, धृतकुमारी आदि और भी बहुत से नामों से जाना जाता है। इसका इस्तेमाल प्राचीन काल से ही औषधि के रूप में किया जाता रहा है। एलोविरा जैल में 20 मिनरल्स, 12 विटामिन्स, 18 अमीनो एसिड्स और 200 प्रकार के न्यूट्रियन्ट्स पाएं जाते हैं। लोग इसका इस्तेमाल सेहत से जुड़ी बहुत सी समस्याओं के लिए करते हैं। इसके साथ ही ब्यूटी से जुड़ा कोई भी हर्बल प्रॉडक्ट हो इसके बिना नहीं बनता। इसी कारण इसे चमत्कारी औषधि भी कहा जाता है।

बालों के लिए एलोविरा के फायदें

रूसी से छुटकारा

रूसी बाल झडने का सबसे बड़ा कारण है। एंटी डैड्रफ शैंपू कुछ समय के लिए तो बालों से रूसी को राहत दिला देते हैं लेकिन इस्तेमाल करने के बाद दोबारा फिर से यह परेशानी होनी शुरू हो जाती है। ऐसे में एलोविरा रूसी को पूरी तरह खत्म कर सकता है। एलोविरा के जूस में थोड़ा-सा नींबू का रस और ऑलिव ऑयल मिलाकार बालों पर लगाए और 15-30 मिनट बाद धो लें।

हेयर ग्रोथ के लिए

एक कप एलोविरा जैल में 2 चम्मच मेथी का पाउडर, 1 चम्मच कैस्टर ऑयल डाल कर मिक्स कर लें। इसे बालों पर मास्क की तरह लगाएं और 1 घंटे बाद बाल धो लें और हफ्ते में 2 बार इसका इस्तेमाल करें।

प्याज और एलोविरा

एलोविरा जैल और प्याज को बराबर मात्रा में मिला कर बालों की जड़ों में लगाएं। एक घंटे तक बालों में लगा रहने के बाद शैंपू से धो लें।

शहद और एलोविरा

बालों में किसी भी तरह की इंफैक्शन है तो एलोविरा जैल में शहद मिलाकर बालों की जड़ों में लगाएं। इसे आधा घंटा लगा रहने के बाद धो लें। इससे बहुत फायदा मिलेगा।

उनकी सुंदरता को और बढ़ा देते है। इस तरह की चीक बोन्स पर मेकअप और भी अच्छे से उभर कर आता है। आजकल हर लड़की करीना की तरह ही चीक बोन्स पाना चाहती है ताकि वह भी परफैक्ट लगें। आज हम आपको करीना की तरह डिफाईन शेप वाले चीक बोन्स बनाने के तीन आसान टिप्स बताएंगें, जिन्हें अपनाकर आप अपनी खूबसूरती पर चार चांद लगा सकती हैं। तो आइए जानते है करीना की तरह क्यूट चीक बोन्स पाने के आसान स्टेप।

सामान-

ब्रॉन्जर के लिए स्किन टोन क्रीम या पाउडर
शिमरी ब्लश
हाईलाइटर

स्टेप 1

सबसे पहले चीक्स को अंदर की तरफ सिकोड़ लें। अब एक एंगुलर ब्रश से गालों पर ब्रॉन्जर लगाएं। ब्रॉन्जर को हेयरलाइन की तरफ ले जाकर ब्लेंड करें। अगर आपका माथा चौड़ा है तो आप ब्रॉन्जर को वहां पर भी अप्लाई करें।

स्टेप 2

दूसरे स्टेप में अपनी चीक बोन्स को हाईलाइट करें। ऐसा करने से मेकअप उभर कर आएगा और आप पहले से ज्यादा खूबसूरत लगेंगी।

स्टेप 3

इसके बाद अपने एप्पल ऑफ चीक्स में शिमरी ब्लश लगाएं। इससे गाल खूबसूरत लगने के साथ ही नैचुरल भी लगेंगे।

दैनिक मुंबई हलचल
अब हर सच होगा उजागर

राम मंदिर पर फिल्म बनाएंगी कंगना

फिल्म इंडस्ट्री में अपनी ऐक्टिंग के लिए मशहूर ऐक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी बेबाकी के लिए भी जानी जाती हैं। कंगना रनौत का अपनी फिल्मों का चुनाव भी अलग ही रहता है। अब कंगना रनौत ने घोषणा की है, वह राम मंदिर मुद्दे पर फिल्म बनाएंगी। इस फिल्म का नाम 'अपराजित अयोध्या' होगा। यह फिल्म कंगना रनौत का प्रॉडक्शन हाउस बनाएगा। राम मंदिर कोर्ट केस पर आधारित फिल्म 'अपराजित अयोध्या' उनके प्रॉडक्शन हाउस की पहली फिल्म होगी। इस फिल्म की अगले साल शुरूआत होगी। बाहुबली सीरीज के निमार्ता केवी विजयेंद्र प्रसाद फिल्म का निर्देशन करेंगे। कंगना रनौत का कहना है कि राम मंदिर सैकड़ों साल से चर्चित मुद्दा रहा है। 80 के दशक में पैदा हुए बच्चे के रूप में मैं अयोध्या का नाम निगेटिव लाइट में सुनकर बड़ी हुई हूं। इस मामले ने भारतीय राजनीति का चेहरा बदल दिया और फैसले ने भारत में सदियों पुराने विवाद को समाप्त कर दिया है। यह मुद्दा एक तरह से मेरी पर्सनल जर्नी को दिखाता। इसलिए मैंने फैसला किया मेरे प्रॉडक्शन हाउस के लिए यह सबसे सही विषय होगा। बता दें कि हाल ही में कंगना रनौत की फिल्म 'थलाइवी' का फर्स्ट लुक टीजर और पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। यह फिल्म तमिलनाडु की दिवंगत पूर्व सीएम जयललिता की जिंदगी पर आधारित है, जिसमें कंगना जयललिता के किरदार को निभाते हुए नजर आएंगी। 'थलाइवी' 26 जून 2020 को रिलीज होगी।

अक्षय ने बताया करीना के साथ फिल्में करने का अनुभव

फिल्म 'ऐतराज' और 'कमबख्त इश्क' में काम करने के बाद करीना कपूर और अक्षय कुमार की जोड़ी फिर से एक साथ दिखाई देने जा रही है। दोनों स्टार फिल्म 'गुड न्यूज' में एक साथ नजर आने वाले हैं। अक्षय कुमार ने हाल ही में करीना कपूर के साथ शूटिंग के अनुभव के बारे में बात करते हुए कहा कि बेबो के साथ फिल्में बनाना किसी वाइल्ड पिकनिक पर जाने जैसा है। ऐक्टर ने कहा कि वह हर बात में शानदार हैं। अक्षय कुमार ने कहा कि करीना कपूर एक चुटकी में मम्मी, दोस्त और को-स्टार बन जाती हैं। उन्होंने कहा कि वह जानते हैं कि उनके फैंस करीना कपूर और उन्हें एक साथ देखने का इंतजार कर रहे हैं। इस समय हम दोनों के लिए इस फिल्म से अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। राज मेहता के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार, करीना कपूर, दिलजीत दोसांझ और कियारा आडवाणी हैं।

'नो एंट्री' के सीक्वल में काम नहीं करेंगे सलमान

पिछले काफी वक्त से ऐसी खबरें आ रही थीं, जिनमें कहा जा रहा था कि सलमान 'नो एंट्री' के सीक्वल यानी 'नो एंट्री में एंट्री' में नजर आएंगे। हालांकि सलमान की तरफ से न तो इसे लेकर कुछ कन्फर्म था और न ही ऑफिशल। लेकिन अब कन्फर्म हो चुका है कि सलमान 'नो एंट्री' के सीक्वल में नहीं होंगे। एक लीडिंग न्यूज वेबसाइट के अनुसार, सलमान ने इस फिल्म से अपना नाम हटा लिया है। बता दें कि 'नो एंट्री' के सीक्वल को बोनी कपूर और अनीस बज्मी मिलकर बनाने वाले हैं। पिछले काफी वक्त से वह सलमान की डेट्स के इंतजार में थे। लेकिन अब सलमान इस फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे। अब इसके पीछे असल वजह क्या है, इसके बारे में तो कुछ नहीं पता। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सलमान के 'नो एंट्री में एंट्री' से निकलने के पीछे अर्जुन कपूर वजह हैं। दरअसल ऐसी खबरें हैं कि बोनी 'नो एंट्री' के सीक्वल में अपने बेटे अर्जुन को भी ले रहे हैं। चूंकि अर्जुन का अफेयर सलमान की पूर्व भाभी मलाइका से चल रहा है। इसलिए सलमान इस फिल्म में काम करने के लिए जरा भी तैयार नहीं हैं। सलमान के रिश्ते मलाइका से उसी वक्त से बिगड़ गए, जब से उनके भाई अरबाज से उनका तलाक हुआ।